

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 7 अप्रैल, 1986

सं० ओ० बि०/एफ०डी०/120-86/12316.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० आई० ए० पी० सी०, प्लॉट नं० 45, सेक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांझनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री हरि चन्द, पुत्र श्री चांदी राम की श्राविक बुद्धि रोकने की सजा न्यायोचित है और क्या श्रमिक निरन्तरित मजदूरी का पूर्ण बतन पाने का हकदार है? यदि ऐसा है तो किस विवरण से ?

मुख्यमन्त्र सिद्ध,

विद्यमान एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 21 मार्च, 1986

सं० ओ० बि०/एफ० डी०/11169.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० गुडगाँवा सेंट्रल कोलोनिज बैंक लि०, गुडगाँवा के श्रमिक श्री चान खान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांझनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पकड़े हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम-87/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री चान खान, पुत्र श्री साई खान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 7 अप्रैल, 1986

सं० ओ० बि०/पानो/20-86/12290.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० काहन उद्योग, ई-33-बी०, इन्डस्ट्रीय एरिया, पानीपत, के श्रमिक श्री राम मेवाज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांझनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम मेवाज, पुत्र श्री राम प्ररण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

मे० पी० रतन,

उप सचिव हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग।